

No. 210/XXXVI(3)/2018/25(1)/2018

Dated Dehradun, April 23, 2018

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Flood Plain Zoning (Amendment) Act, 2018' (Adhiniyam Sankhya: 22 of 2018).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 19 April, 2018.

The Uttarakhand Flood Plain Zoning (Amendment) Act, 2018

(Uttarakhand Act No. 22 of 2018)

An

Act

further to amend The Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 (Uttarakhand Act. 07 of 2013)

Enacted by the Uttarakhand State Assembly in the 69th Year of the Republic of India

Short title, extant and Commencement	1. (1)	This Act may be called the Uttarakhand Flood Plain Zoning (Amendment) Act, 2018.
	(2)	It extend to the whole of the State of Uttarakhand.
	(3)	It shall come into force at once.
Amendment of Section 12	2.	In Proviso to subsection (1) of Section 12 of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 (Uttarakhand Act No. 07 of 2013), the words "six month" shall be substituted by the words "eighteen month"

By Order,

Meena Tiwari,
Principal Secretary.

उद्देश्य और कारणों का कथन

उत्तराखण्ड राज्य में नदियों के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के लिए उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 8 में बाढ़ मैदान क्षेत्रों को चिन्हित करने के राज्य सरकार के आशय की घोषणा करने की शक्ति दी गयी है। इसी प्रकार धारा 12 की उपधारा (1) में बाढ़ मैदानों में गतिविधियां प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गयी है। इस धारा के परन्तुक में इस प्रकार की कोई अधिसूचना धारा 8 के अधीन जारी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छः मास के समाप्ति के पश्चात किए जाने पर प्रतिबंध है। छः माह की समय सीमा अत्यंत न्यून है अतः राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि उक्त छः मास की अवधि को अठारह मास की अवधि नियत कर लिया जाए।

2- प्रस्तुत विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।